

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 अगस्त, 2001/31 भावण, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

शिमला-4, 22 अगस्त, 2001

अधिसूचना

संख्या 1-57/2001-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय (मंशोबन) विनियम, 2001 (2001 का

1384-राजपत्र/2001-22-8-2001—1,343.

(2021)

मूल्य : 1 रुपया।

बिधेयक संख्यांक 16) को आज दिनांक 22 अगस्त, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है। सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,  
सचिव।

## हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2001 है।

संक्षिप्त  
नाम और  
प्रारम्भ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

1976 का  
23.

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 में, शब्दों, "पांच लाख" के स्थान पर, "दस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10 का  
संशोधन।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने 27-3-2001 को हुई इसकी बैठक में, जिला न्यायालय की धन सम्बन्धी आरम्भिक अधिकारिता में पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए की वृद्धि अनुमोदित कर दी है और हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 में संशोधन की सिफारिश की है।

अतः पूर्वोक्त अधिनियम में, जिला न्यायालय की धन सम्बन्धी आरम्भिक अधिकारिता को, पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए करने के लिए संशोधन करने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख..... 2001.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

**हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2001**

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

प्रेम कुमार धूमल,  
मुख्य मन्त्री ।

रामदेवर शर्मा,  
सचिव (विधि) ।

शिमला :

....., 20 01.

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT)  
BILL, 2001

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2001.

Amendment  
of section 10.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, for the words “five lakh”, the words “ten lakh” shall be substituted.

23 of 1976.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in its meeting held on 27-3-2001 has approved the enhancement of pecuniary original jurisdiction of the District Courts from rupees five lakh to ten lakh and have recommended the amendment in section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976. Hence, it has been decided to make amendment in the Act *ibid* to enhance the pecuniary original jurisdiction of the District Courts from five lakh to ten lakh rupees.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

PREM KUMAR DHUMAL,  
*Chief Minister.*

SHIMLA :

*The.....*2001.

## FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

## THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2001

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).*

PREM KUMAR DHUMAL,  
*Chief Minister.*

RAMESHWAR SHARMA,  
*Secretary (Law).*

SHIMLA:  
*The.....2001.*